

सुरंग में फंसे श्रमिक बचाव के प्रयास

सुरंग में फंसे श्रमिकों के बहुआयामी बचाव प्रयास जारी हैं। नौ दिन से 41 निर्माण कर्मी उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे हैं और वे सामान्य जीवन की तरह सूरज के प्रकाश तथा हवा से वंचित हैं। 12 नवंबर को सिल्व्यारा-बारकोट निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंस गया था जिसमें ये श्रमिक फंस गए थे। अनेक सरकारी एजेंसियों ने उनको बचाने के लिए सर्वोत्तम मशीनरी का प्रयोग किया है, लेकिन उनको अब भी यहां से निकाला नहीं जा सका है। मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश व झारखण्ड के इन श्रमिकों का रास्ता मलबे और पथरों से पट गया है। इस दुर्घटना में इन कर्मियों की ढूढ़ता की परीक्षा हो रही है और इसके साथ ही यह उनको बचाने के व्यापक व समन्वित प्रयासों की भी परीक्षा है। यह सुरंग प्रधानमंत्री ने इन मोदी सरकार की 'चार धार' तक सभी मौसमों में पहुंचने की परियोजना का हिस्सा है। सुरू पहाड़ी क्षेत्र में बचाव टीमों को भयानक लाजिस्टिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने फौरन फंसे कर्मियों को बाहर निकालने के लिए अनेक एजेंसियों को काम पर लगाया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-एनडीआरएफ की विशेष टीमें, स्थानीय पुलिस तथा विदेशी विशेषज्ञों को दुर्घटना स्थल पर तैनात किया गया है। बचाव कार्य नौ दिन से जारी हैं, पर अभी इनका कोई नतीजा नहीं निकला है। शुरुआती बचाव प्रयासों को 17 नवंबर को रोकना पड़ा था, जब कर्मियों को बाहर निकालने के लिए मलबे में नया पाइप डालने के समय सुरंग से भयानक आवाज सुनाई दी थी। कर्मियों को भोजन, पानी और दवाएं पहुंचाने के लिए पाइपों का प्रयोग किया जा रहा है।

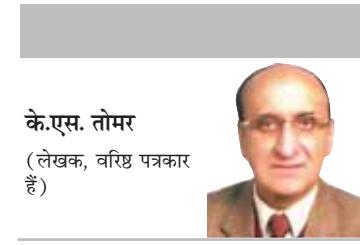
विडंबना है कि मिट्टी को हटाने के लिए भारी मशीनों के प्रयोग से समस्या और गंभीर हुई है क्योंकि इसके कारण और मलबा पिरा जिसने उनके बाहर निकलने का संभावित रास्ता बंद कर दिया। हालांकि, यह समय इस मुद्दे



पर विचार करने का नहीं है कि ऐसी विशाल परियोजनाओं को संवेदनशील परिस्थितिकी में अनुमति दी जानी चाहिए थी या उसके लिए समुचित सुरक्षा व संरक्षा उपाय अपनाए गए थे, लेकिन इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता जरूर है। दुर्गम क्षेत्र के निवासियों तथा पर्यटकों को आधुनिकतम सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार है और इसे यथासंभव उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। हालांकि, इस घटना में स्वार्थिक सकारात्मक और उत्साहजनक नतीजों लोगों की परायर सहायता की प्रवृत्ति है। फंसे कर्मियों की खबर फैलते ही स्थानीय समुदाय ने एकजुट होकर बचावकर्मियों तथा कर्मियों के परिवारों को सहायता दी। स्थानीय स्वयंसेवकों ने वर्तमान कार्रवाइयों तथा बचाव प्रयासों में शामिल लोगों को भोजन, शरणस्थल व नैतिक समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सभी लोग सांस रोक कर असहाय फंसे श्रमिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो किसी अन्य के लालच और लापरवाही का शिकार हुए हैं। हालांकि, बचाव प्रयासों की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर हो रही है, प्रधानमंत्री ने नेट्रो मोदी लगातार उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर संपर्क में हैं, सुरुंगों में फंसे श्रमिकों को बचाने में विशेषज्ञा वाली कई विदेशी एजेंसियों के विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गए हैं तथा कई केन्द्रीय मंत्री घटनास्थल पर जाकर राहत प्रयासों का आंकलन कर चुके हैं। इन मंत्रियों में नितिन गडकरी तथा सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह शामिल हैं। आशा है जल्द ही फंसे श्रमिकों को मुक्ति मिलेगी।

मोदी के करिश्मे पर निर्भर भाजपा

अब यह पूर्णतः स्पष्ट है कि भाजपा आलाकमान व आरएसएस पांच राज्य विधानसभा चुनावों में विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'करिश्मे' पर निर्भर है।



प्रधानमंत्री ने रन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं से भाजपा को विजय के लिए दिलाने की व्यक्तिगत अपील की है। इसके साथ ही किसी नेता को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने का निष्पत्र भी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अब भारतीय जनतां पार्टी-भाजपा पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर अत्यधिक निर्भर है। नवंबर में हो रहे राज्य विधानसभा चुनावों में विजय या पराजय तथा उसके भावी राजनीतिक परिणामों पर विश्लेषकों की राय अलग-अलग है। एक प्रकार के विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा इन चुनावों में विजय प्राप्त करती है तो उसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यक्तिकौन केन्द्र सरकार के लिए घोट देने के समय मतदाताओं की राय अलग हो सकती है। अतीत पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि भाजपा को 2018 में हिंदी पट्टी के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था, पर वह 2019 के लोकसभा चुनाव में 65 सीटों में से 61 पर विजय पाने में

सफल हुई थी। इनमें उसे राजस्थान की 25 सीटों में से 24, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 तथा छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 लोकसभा सीटों पर मिली विजय शामिल है 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के मिली विजय का मुख्य कारण 'मोदी लहर तथा उसका राष्ट्रवादी एजेंडा था।

वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता बहुत उच्च स्तर पर है और भारत के मतदाताओं में उनकी स्वीकार्यता अधिकतम है। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा को उसके 'हिंदुत्व एजेंडे' का लाभ मिलेगा। जनवरी में अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का श्रीगणेश होने के बाद उसका यह एजेंडा और शक्तिशाली बन जाएगा। भाजपा इसका पूरी तरह लाभ उठाने का प्रयास करेगी। भाजपा के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-आरएसएस अपनी व्यापक व सुसंगठित संगठन शक्ति से लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की विजय सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं



छोड़ेगा। भाजपा मतदाताओं को राजग सरकार की शानदार उपलब्धियों तथा मोदी के मजबूत नेतृत्व की बात समझाने का प्रयास करेगी। मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करना तथा संसद में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाना संभव हुआ है। इसके उलट आलोचकों का विश्वास है कि यदि भाजपा राज्य विधानसभा चुनावों में पराजित होती है तो संसदीय चुनावों में भी उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। आलोचकों की नजर में ऐसे कई महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनसे भाजपा की गणित बिगड़ जाएगी। पहला, इस बार कोई पुलवामा या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मामला नहीं है जिसने देशव्यापी राष्ट्रवाद का उभार पैदा किया था। दूसरा, उस समय कांग्रेस तथा विपक्षी पार्टियों की लोकप्रियता सबसे निचले बिंदु पर थी व्यावेक मतदाताओं की नजर में वे भाजपा का विकल्प नहीं थे। तीसरा, इस बार मोदी का 'करिश्मा' राजग सरकार के नौ-वर्षीय शासन के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर को निष्प्रभावी करने के लिए काफी नहीं होगा। चौथा, आम लोग आवश्यक वस्तुओं की आसान छूटी कीमतों का सामना कर रहे हैं जिससे उनका जीवन कठिन हो गया है। पांचवां, नौजवानों ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिए थे, पर अब बेरोजगारी की समस्या शिखर पर है जिससे समाज पर प्रभुत्व खड़ने वाला यह तबका बहुत नाराज है। छठा, मध्य वर्ग प्रभावित है और उसकी प्रतिक्रिया 2019 से उलट हो

की उपर्युक्ती है। सातवां, कर्नाटक में कांग्रेस की वज्रय तथा तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक द्वारा आजपा से संबंध तोड़ने से भाजपा को धक्का दिया गया है। दक्षिण भारत में समुचित संख्या में चीटीं जीत बिना भाजपा सत्ता तक नहीं पहुंच सकती है। इन सभी चीजों के साथ ही विपक्षी पार्टियां अई.एन.डी.आई.ए की छतरी ले एक जुट हो गई हैं। इसके साथ ही विपक्ष अपने नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों कथित दुरुपयोग का मामला उठाया है। आलांकि विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार ने घोषणा करना बहुत कठिन है, पर वे नेटोटैरू से सीटों के साझे के साथ एक दूसरे खिलाफ उम्मीदवार खड़े न करने का मामला कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में 2024 अपूर्व देश में उनके बोटों की गणित प्रभावी रूप सकती है।

मुख्यमंत्री शिवगांज चौहान पर लगाम लगाने के लिए भाजपा आलाकमान ने अपने केन्द्रीय मंत्रियों, जैसे नेरन्द्र सिंह तोमर, पहाद शंसंह पटेल व फगन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतार कर मतदाताओं को आश्चर्यचिकित किया। इनको मध्य प्रदेश चुनाव में उम्मीदवारों की पहली सूची में स्थान दिया गया। भाजपा की रणनीति के अनुसार केन्द्रीय मंत्रियों का पूरे राज्य में प्रभाव हो सकता है, आलांकि उनको अभी जनता के बीच अपनी अज्यव्यापी लोकप्रियता सिद्ध करनी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मंत्री या अंसद विरले ही खास निर्वाचन क्षेत्रों में बाइक्रो-स्तरीय प्रबंधन करते हैं और यह

प्रदेश में उनके लिए चिन्ता का कारण सकता है। शिवराज चौहान की तुलना में का राज्य-स्तरीय कद नहीं हो सकता है, कि चौहान स्वयं को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घेत न करने से नाराज हैं। शायद भाजपा नाकमान और आरएसएस के सर्वोच्च ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पार्टी का राजा बना कर और चुनाव वाले राजस्थान, प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की घोषणा न कर दी की है। लेकिन एक अलग विश्लेषण अधार पर भाजपा ने नाया प्रयोग किया है। ने एक खास राजनीति के अंतर्गत मध्य राज्यों के राजस्थान व छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में 24 सांसदों व 4 केन्द्रीय मंत्रियों को नाम देती है। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय सुनिश्चित करने के लिए जपा की 'प्रतिबद्धता' स्पष्ट होती है। जपा पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में विजय प्राप्त कर यह विमर्श मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इसका उद्देश्य मतदाताओं की वर्तमान रायकों के प्रति पैदा नाराजी दूर करने का हो सकता है। मतदाता निर्वाचन क्षेत्रों उतारे गए सांसदों और मंत्रियों को 'नए नए' मान कर उनको पुनः विजयी बनाने का य कर सकते हैं।

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश नासभा चुनावों के नतीजों से प्रधानमंत्री द्वारा मोदी के व्यापक अभियान को धक्का लग सकता है तथा 'हिंदुत्व' भी आशानुकूल भाजपा कांग्रेस को राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ की सत्ता से हटाने में विफल होती है तथा तेलंगाना में सी. चंद्रशेखर राव की 'भारत राष्ट्र समिति'-बीआरएस सत्ता में बड़ी रहती है तो इसका असर 2024 में होने वाले संसदीय चुनावों पर पड़ सकता है। लेकिन यदि पांच राज्यों के राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा की अपेक्षानुसार नतीजे आते हैं तो इसका दोगुना असर पड़ सकता है। राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा की विजय से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विजय पूर्णतः सुनिश्चित हो जाएगी और वे प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि भाजपा के 'थिंक टैंकों' ने केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नौ साल चली सरकार के प्रदर्शन और उसके द्वारा किए जन-कल्याण कार्यों का व्यापक आंकलन किया है। उनका विश्वास है कि इसका लाभ राज्य विधानसभा चुनावों में भी पार्टी के उम्मीदवारों को मिल सकता है। भाजपा ने 'गुजरात माडल' के आधार पर पुरानी पौदी के नेताओं को हटाकर उत्तराखण्ड, गोवा और त्रिपुरा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए, पर यह प्रयोग कर्नाटक में बुरी तरह विफल हुआ अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव में केन्द्रीय मंत्रियों व सांसदों के उत्तराने से पार्टी को लाभ होता है या इसके

परिणाम

जाए रखने के लिए दूसरों की भू-जनीतिक ताकत को कमज़ोर करने के लिए बरेत कर रही हैं। हरित औद्योगिकरण का क्रेन में युद्ध, जिसके परिणामस्वरूप गैस प्रौद्योगिकी में अनिश्चितता पैदा हुई, ने यूरोप के लिए अपने नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन में जी लाने के लिए प्रक्रियावाणी के रूप में राजनीतिक विश्व व्यवस्था में सुचारू परिवर्तन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व हैं: सकते हैं: न्यायसंगत और निष्पक्ष परिवर्तन, फंसे हुए कार्बन परिसंपत्तियों के मुआवजे के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक अव्यवस्था को कम करना और नौकरी की गतिशीलता के अवसर पैदा करना।

बहुपक्षवाद का पुनरुद्धार: वैशिक संस्थानों को निहत स्वार्थी गठजोड़ को तोड़ने और तजें से कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन बनाने के लिए पहले से कहीं अधिक सहयोग करने की आवश्यकता है। तकनीकी छलांग: ओपन-सोस तकनीकी सफलताएं ऊर्जा क्षमताओं के आधार पर बिजली के नए क्षेत्रों के निर्माण को रोक सकती हैं और एक नई विश्वव्यवस्था बना सकती है। उभरते देशों में शक्ति का प्रसार - वैशिक आर्थिक विकास के भविष्य के केंद्रों को ध्यान में रखते हुए और इसलिए उभरते देशों में ऊर्जा की खपत को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवाज़ को वैशिक शक्ति समीकरणों में एक केंद्रीय स्थान खोजने की आवश्यकता है।

वसरे प्रदान करते हैं। एक नई मूँ- आवश्यकता है।

प्रकृति का संरक्षण

यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुगम बनाने हेतु बनाए जा रहे सुरंगी मार्ग में 41 श्रमिक एक सप्ताह से पहले हुए हैं। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र में किए गए और हो रहे निर्माण कार्यों को पूर्ण सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। विडंबना है कि कई बार ऐसे प्रकरणों का खामियाजा भुगतने के बाद भी पहाड़ों में निर्माण कार्य, पहाड़ों की खोदाई और वृक्षों की कटाई जारी है। वस्तुतः ऐसे कार्य स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसे हैं। यह स्वयं प्रकृति के साथ ज्यादती है। यदि हम प्रकृति व पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर सकते तो अपनी सुविधा या कामाई हेतु उसका क्षरण या उसके साथ ज्यादती तो न करें। ऐसा न करने पर हमें प्रकृति की नाराज़गी सहन करने को तैयार रहना चाहिए। पहाड़ों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर निजी या सरकारी निर्माण कार्यों में पर्यावरण संरक्षण को बरीयता मिलनी चाहिए। पर्यटकों की संख्या बढ़ा कर अथवा उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं देने से तीर्थयात्रा के प्रति प्राचीन भावना भी एक प्रकार से आहत होती है, जब तीर्थयात्रा का अर्थ तपस्या और कष्ट-सहन भी होता था।

- बी एल शर्मा, उज्जैन

प्रकृति का संरक्षण

काम और आराम

काम के बीच ब्रेक लेने या आराम का पफ्यदा जापानियों के साथ-साथ अन्य कई देशों में लिया जा रहा है। मगर वहाँ से भारत की परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ तो आदमी काम के प्रति कर्तव्य ईमानदार नहीं हैं। यथासंभव हर काम को टालना अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की प्रवृत्ति बन गई है। यहाँ तक कहा जाने लगा है कि हमारे यहाँ अनेक सरकारी अधिकारी तनखाह के बदले आराम करते हैं और रिश्त के बदले काम करते हैं। इसके अलावा लंबं ब्रेक तो होता ही है जिसमें खाना खाने के बाद कुछ लोग ज्यादा आराम करने लगते हैं। ४ घंटे की डयरी में हमारे यहाँ वैसे ही दो-तीन घंटे काम होता है। उस पर यदि ब्रेक लेने की छूट दे दी जाए तो सारे काम का बांधधार हो जाएगा। यदि अपने काम के प्रति पूरे समर्पित होकर आनंदपूर्वक कार्य किया जाए तो वैसे भी थकान नहीं होगी और सफेद पोश नौकरियों में ब्रेक के रूप में कुछ व्यायाम का प्रावधान उचित होगा। जब नारायणमूर्ति ने सत्ताह में ७० घंटे काम का सुझाव दिया तो उसे हवा में उड़ा दिया गया और जल्द ही भुला भी दिया गया। वैसे भी-आराम हराम का नारा देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू आज ज्यादातर लोगों की स्मृतियों से बाहर हो गए हैं।

- सभाष बड़ावन वाला, रत्नाम

पक्षपात की आशंका

हाल ही में एक बार फिर बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को तीन सप्ताह की बेल प्रदान की गई है। गुरमीत राम रहीम सिंह को अगस्त 2017 में पंचकुला में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत ने दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराया था। उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गयी है। लगता है सजा पूरी होते-होते उन्हें 20 महीनों का बेल प्रदान कर दिया जायेगा। इसके उलट महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले में कई बुजुर्गों को उनकी विचारधारा एवं सोच के कारण 2008 से ही जेल में रखा गया है। उनका बेल अपील को अदालतों द्वारा बार-बार ठुकरा दिया जाता है। एक बुजुर्ग फदर स्टेन स्वामी को लगातार जेल में रखा गया। इस कारण समुचित इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। ऐसे प्रकरणों से आम लोगों में शासन सत्ता और न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होती है। इससे यह आशंका भी पैदा होती है कि वोटबैंक अथवा अन्य कारणों से कुछ खास लोगों के साथ पक्षपात कर उनको ज्यादा रियायत दी जा सकती है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

आप की बात

ई-फार्मेसी

चलते ई-
च्छे दिन आ
क किलक से
पहुंच जाती
फर्मेसी का
लिए किया
आसानी से
बुजुगों और
लाए भी ई-
योग किया
मध्यम से
किस्म की
दवा उद्योग
दिल्ली हाई
कोर्ट ई-फार्मेसी
दिया है।

पिछले पांच साल से आनलाइन दवाओं की बिक्री पर कई स्पष्ट नीति नहीं है। ई-फर्मेसी नीति की समय सीमा अगले आठ सप्ताह तय की गई है। न्यायालय ने कहा है कि ड्राप एंड कॉस्मेटिक एक्ट और फर्मेसी एक्ट, 1948 के तहत इसकी अनुमति नहीं है। यदि सरकार ई-फार्मेसी को अनुमति देती है तो उसे आफलाइन दवा विक्रेताओं को भी कठोर एवं अव्यावहारिक नियंत्रण से मुक्ति की दिशा में कदम उठाने चाहिए। दवा विक्रेता इसकी लंबे समय से मांग करते हुए कई बाहर हड़ताल भी कर चुके हैं।

- दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुगम बनाने हेतु बनाए जा रहे सुरंगी मार्ग में 41 श्रमिक एक सप्ताह से पूर्ण हुए हैं। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र में किए गए और हो रहे निर्माण कार्यों को पूर्ण सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। विडंबना है कि कई बार ऐसे प्रकरणों का खामियाजा भुगतने के बाद भी पहाड़ों में निर्माण कार्य, पहाड़ों की खोदाई और वृक्षों की कटाई जारी है। वरदुतः ऐसे कार्य स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसे हैं। यह स्वयं प्रकृति के साथ ज्यादती है। यदि हम प्रकृति व पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर सकते तो अपनी सुविधा या कमाई हेतु उसका क्षरण या उसके साथ ज्यादती तो न करें। ऐसा न करने पर हमें प्रकृति की नाराजगी सहन करने को तैयार रहना चाहिए। पहाड़ों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर निजी या सरकारी निर्माण कार्यों में पर्यावरण संरक्षण को बरीयता मिलनी चाहिए। पर्यटकों की संख्या बढ़ा कर अथवा उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देने से तीर्थयात्रा के प्रति प्राचीन भावना भी एक प्रकार से आहत होती है, जब तीर्थयात्रा का अर्थ तपस्या और कष्ट-सहन भी होता था।

- बी एल शर्मा, ऊज़ैन

